



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 192]
No. 192]नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 2, 2010/श्रावण 11, 1932
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 2, 2010/SHRAVANA 11, 1932

दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन
(छठा संशोधन) विनियम, 2010

(2010 का संख्यांक 4)

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2010

फा. सं. 6-7/2010-बीएंडसीएस.—भारत सरकार, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग) की अधिसूचना सं. 39 जो,—

- (क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (ट) के परंतुक तथा धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (घ) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई थी, तथा
- (ख) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 में दिनांक 9 जनवरी, 2004 की अधिसूचना संख्या का.आ. 44(अ) और 45(अ) के तहत प्रकाशित हुई थी,

के साथ पठित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 36 द्वारा तथा धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (ii), (iii), (iv) और (v) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन विनियम, 2004 (2004 का 13) में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. (1) इन विनियमों को दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (छठा संशोधन) विनियम, 2010 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन विनियम, 2004 (2004 का 13) (जिसे इसमें इसके पश्चात प्रधान विनियम कहा गया है) के विनियम 2 में,-

(क) उप-खंड (ठ) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(ठ) "हैड एंड इन द स्काई प्रचालक" अथवा "हिट्स प्रचालक" से अभिप्रेत है केंद्रीय सरकार द्वारा निम्न के लिए अनुमति प्राप्त कोई व्यक्ति -

(क) सी-बैंड अथवा केयू बैंड में निम्न के लिए मल्टी चैनल टीवी कार्यक्रमों का वितरण -

(i) उपग्रह प्रणाली का प्रयोग करते हुए मध्यस्थों, जैसे केबल प्रचालकों को और सब्सक्राइबरों को सीधे नहीं, और

(ii) अपने स्वयं के केबल नेटवर्क, यदि कोई है, का प्रयोग करते हुए ऐसे केबल नेटवर्क के सब्सक्राइबरों को पहले अपने स्थलीय प्राप्तकर्ता स्टेशन पर सिग्नलों की डाउनलिंकिंग करने के पश्चात् क्वाइक्रेचर एम्पीट्र्यूड मोडुलेशन (क्यूएम) सेट टॉप बॉक्सों के माध्यम से; और

(ख) ऐसी अवसंरचनात्मक सुविधाओं का प्रयोग करते हुए क्यूएम सेट टॉप बॉक्सों के माध्यम से सी-बैंड अथवा केयू बैंड में मल्टी चैनल टीवी कार्यक्रमों के वितरण के लिए, एक अथवा अधिक मल्टी सिस्टम प्रचालकों अथवा मल्टी सिस्टम प्रचालकों या केबल प्रचालकों के किसी कंसोर्टियम को पैसिव अवसंरचनात्मक सुविधाएं जैसे ट्रांसपोर्डर स्पेस ऑन सेटेलाइट, अर्थ स्टेशन सुविधाएं आदि प्रदान करना;

(ख) उप-खंड (ड) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः—

(ड) “मल्टी सिस्टम ऑपरेटर” से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो, प्रसारकों से अथवा उनकी प्राधिकृत एजेन्सियों से अथवा हैडेंड इन द स्काई प्रचालकों से कार्यक्रम सेवा प्राप्त करता है और एक या एक से अधिक केबल ऑपरेटरों को अथवा उपभोक्ताओं को अथवा दोनों को, उसका रि-ट्रांसमिशन करता है तथा इनमें शामिल हैं उसकी प्राधिकृत वितरण एजेन्सियां;”।

3. प्रधान विनियमों के विनियम 3 में,—

(क) उप-विनियम 3.2 में, “मल्टी सिस्टम प्रचालक, अनुरोध पर, किसी प्रसारक से प्राप्त सिगनलों को, गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर, केबल प्रचालक को भी रि-ट्रांसमिट करेगा” अभिव्यक्ति के स्थान पर निम्नलिखित अभिव्यक्ति प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“हिट्स प्रचालक अथवा मल्टी सिस्टम प्रचालक, अनुरोध पर, किसी प्रसारक से प्राप्त सिगनलों को, गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर, केबल प्रचालक को भी रि-ट्रांसमिट करेगा”;

(ख) उप-विनियम 3.5 में, “प्रसारक/मल्टी सिस्टम प्रचालक” अभिव्यक्ति, जहां कहीं आती है, के स्थान पर “यथास्थिति, प्रसारक, मल्टी सिस्टम प्रचालक अथवा हिट्स प्रचालक” अभिव्यक्ति प्रतिस्थापित की जाएगी।

4. प्रधान विनियमों के विनियम 4 में, उप-विनियम 4.1 और 4.2 में, “प्रसारक अथवा मल्टी सिस्टम प्रचालक” अभिव्यक्ति, जहां कहीं आती है, के स्थान पर “यथास्थिति, प्रसारक, मल्टी सिस्टम प्रचालक अथवा हिट्स प्रचालक” अभिव्यक्ति प्रतिस्थापित की जाएगी।

5. प्रधान विनियमों के विनियम 13.2क में,—

(क) उप-विनियम 13.2क.1 में, “दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (पांचवां संशोधन) विनियम, 2009 (2009 का 4)” शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और संख्याओं के स्थान पर, “दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (छठा संशोधन) विनियम, 2010 (2010 का 4)” शब्द, अंक, कोष्ठक और संख्याएं प्रतिस्थापित की जाएंगी;

(ख) उप-विनियम 13.2क.2 के परंतुक में, “दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (पांचवां संशोधन) विनियम, 2009 (2009 का 4)” शब्दों, अंकों,

कोष्ठकों और संख्याओं के स्थान पर, “दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (छठा संशोधन) विनियम, 2010 (2010 का 4)” शब्द, अंक, कोष्ठक और संख्याएं प्रतिस्थापित की जाएंगी;

- (ग) उप-विनियम 13.2क.3 और 13.2क.4 में, “दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (पांचवां संशोधन) विनियम, 2009 (2009 का 4)” शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और संख्याओं, जहां कहीं भी वे आती हैं, के स्थान पर, “दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (छठा संशोधन) विनियम, 2010 (2010 का 4)” शब्द, अंक, कोष्ठक और संख्याएं प्रतिस्थापित की जाएंगी;
- (घ) उप-विनियम 13.2क.6 के खण्ड (1), खण्ड (2) और खण्ड (3) में, “दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (पांचवां संशोधन) विनियम, 2009 (2009 का 4)” शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और संख्याओं, जहां कहीं भी वे आती हैं, के स्थान पर, “दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (छठा संशोधन) विनियम, 2010 (2010 का 4)” शब्द, अंक, कोष्ठक और संख्याएं प्रतिस्थापित की जाएंगी।

6. प्रधान विनियमों के विनियम 13.2ख में, उप-विनियम 13.2ख.1 और 13.2ख.2 में, “दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (पांचवां संशोधन) विनियम, 2009 (2009 का 4)” शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और संख्याओं, जहां कहीं भी वे आती हैं, के स्थान पर, “दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (छठा संशोधन) विनियम, 2010 (2010 का 4)” शब्द, अंक, कोष्ठक और संख्याएं प्रतिस्थापित की जाएंगी।

सुबोध कुमार गुप्ता, सलाहकार (बी एंड सीएस)

[विज्ञापन III/4/142/10/असा.]

टिप्पणी 1 : प्रधान विनियम अधिसूचना सं. 8-26/2004-बी एंड सीएस, दिनांक 10 दिसम्बर, 2004 द्वारा प्रकाशित हुए थे तथा इनमें बाद में अधिसूचना सं. 3-57/2005-बी एंड सीएस, दिनांक 3 मार्च, 2005, सं. 11-13/2006-बी एंड सीएस, दिनांक 24 अगस्त, 2006, सं. 6-4/2006-बी एंड सीएस, दिनांक 4 सितम्बर, 2006, सं. 4-54/2007-बी एंड सीएस, दिनांक 3 सितम्बर, 2007 और सं. 3-21/2009-बी एंड सीएस, दिनांक 17 मार्च, 2010 द्वारा संशोधन किए गए।

टिप्पणी 2 : व्याख्यात्मक ज्ञापन दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (छठा संशोधन) विनियम, 2010 के उद्देश्यों और कारणों का वर्णन करता है।

अनुबंध

व्याख्यात्मक ज्ञापन

पृष्ठभूमि:

भारत सरकार (सूचना और प्रसारण मंत्रालय) ने भारत में हैड-एंड-इन-द-स्काई (हिट्स) प्रसारण सेवा प्रदान करने के लिए 26 नवम्बर, 2009 को नीतिगत दिशा-निर्देश घोषित किए थे। हिट्स नीति की उक्त घोषणा के अनुसरण में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपने दिनांक 10 दिसम्बर 2009 के पत्र द्वारा इस संबंध में दृष्टिकोण बनाने कि क्या सेवा हित में उनमें कोई संशोधन अपेक्षित है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) से प्रासंगिक अंतरसंयोजन विनियमों, टैरिफ आदेशों आदि की पुनःसमीक्षा करने का अनुरोध किया ताकि नीति के लाभ पूरी तरह प्राप्त किए जा सकें। उक्त अनुरोध के आधार पर प्राधिकरण ने "हिट्स सेवाओं से संबंधित अंतरसंयोजन और टैरिफ मुद्दों" पर एक परामर्श प्रक्रिया आरंभ की। इस प्रयोजनार्थ, 6 अप्रैल, 2010 को एक परामर्श-पत्र जारी किया गया। परामर्श-पत्र को परामर्श में उठाए गए मुद्दों की दो बहुत श्रेणियों में विभाजित किया गया था अर्थात् अंतरसंयोजन मुद्दे और टैरिफ मुद्दे। टैरिफ संबंधी मुद्दों का निवारण अलग से किया गया है।

परामर्श के लिए मुद्दे:

2. जहां तक अंतरसंयोजन का संबंध है, परामर्श-पत्र में यह उल्लेख किया गया था कि हैड-एंड-इन-द-स्काई प्रचालक" की परिभाषा, जैसीकि दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन विनियम 2004 (2004 का 13) में अंतर्विष्ट है, एक संकीर्ण परिभाषा है जो हिट्स प्रचालकों के प्रचालनों को केवल सी-बैंड में सीमित करती है, जबकि 26 नवम्बर, 2009 को घोषित हुई भारत सरकार की हिट्स नीति में हिट्स प्रचालनों को या तो सी-बैंड में अथवा केयू-बैंड में अनुमति दी गई है। परामर्श-पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि विद्यमान परिभाषा हिट्स प्रचालकों को सब्सक्राइबरों को

3016 G1/10-2

सीधे सेवा प्रदान करने से प्रतिषिद्ध करती है, जबकि नीतिगत दिशा—निर्देश अब हिट्स प्रचालक को पहले उनके स्थलीय प्राप्तकर्ता स्टेशनों पर सिगनलों की डाउनलिंकिंग करने के पश्चात, उनके स्वयं के केबल नेटवर्क, यदि कोई है, के माध्यम से सीधे सब्सक्राइबर को सेवा प्रदान करने की अनुमति देते हैं। सरकार की हिट्स नीति द्वारा लाए गए इन परिवर्तनों ने “हैड-एंड-इन-द स्काई प्रचालक” की परिभाषा, जैसीकि दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन विनियम, 2004 (2004 का 13) में अंतर्विष्ट है, में संशोधन किए जाने की आवश्यकता उत्पन्न कर दी।

3. परामर्श—पत्र में यह भी उल्लेख किया गया था कि चूंकि कोई मल्टीसिस्टम प्रचालक अब न केवल प्रसारकों और उनके प्राधिकृत एजेंसियों से बल्कि एक हिट्स प्रचालक से भी सिगनल ले सकता है, “मल्टी सिस्टम प्रचालक” की परिभाषा में भी संशोधन की आवश्यकता हुई। तदनुसार, परामर्श—पत्र ने इन उपबंधों में अपेक्षित संशोधनों को मोटे तौर पर रेखांकित किया तथा पण्धारकों के साथ परामर्श के लिए निम्नलिखित मुद्दों को उठाया:—

- (i) क्या हिट्स नीति का क्रियान्वयन करने के लिए अंतरसंयोजन विनियमों में प्रस्तावित संशोधन सही है?
- (ii) क्या हिट्स नीति के क्रियान्वयन के लिए अन्य संशोधनों की आवश्यकता भी है?

पण्धारकों की टिप्पणियां:

4. कुल मिलाकर 23 पण्धारकों ने परामर्श—पत्र पर अपनी टिप्पणियां प्रदान कीं। एक पण्धारक ने पण्धारकों से प्राप्त टिप्पणियों पर प्रति—टिप्पणियां भेजी। दिल्ली, पुणे, बंगलुरु और कोलकाता में क्रमशः 1 जून 2010, 3 जून 2010, 4 जून, 2010 और 8 जून, 2010 को ओपन हाउस चर्चाएं आयोजित की गईं।

5. हिट्स नीति के क्रियान्वयन के लिए अंतरसंयोजन विनियमों में प्रस्तावित संशोधनों के उचित होने के मुद्दे पर प्रसारकों और एमएसओ सहित लगभग सभी पण्धारकों ने प्रस्तावित संशोधनों से अपनी सहमति व्यक्त कीं।

6. परामर्श—प्रक्रिया से उभरने वाले सभी मामलों के पहलुओं पर विचार करने के उपरांत प्राधिकरण ने हिट्स प्रचालकों द्वारा सी और केयू दोनों ही बैंडों के प्रयोग करने का उपबंध करने के लिए हिट्स प्रचारकों की परिभाषा में संशोधन करके अंतरसंयोजन विनियम में संशोधन किया है। चूंकि सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी नीतिगत दिशा—निर्देशों में इनके अपने केबल नेटवर्क पर मल्टी चैनल कार्यक्रमों के वितरण (पहले इसके स्थानीय रिसीवर स्टेशन पर सिग्नलों की डाउनलिंकिंग करने के पश्चात) के लिए हिट्स प्रचालकों को अनुमति दी गई है तथा इनमें किसी अन्य एमएसओ अथवा केबल प्रचालकों के कंर्सोटियम को निष्क्रिय अवसंरचनात्मक सुविधा प्रदाता बनने के लिए भी हिट्स प्रचालक को उपबंधित किया गया है, "हिट्स प्रचालक" तथा "मल्टी सिस्टम प्रचालक" की विद्यमान परिभाषा को वृहद भी किया गया है।
7. विनियम 3, 4, 13.2क और 13.2ख में भी परिणामी अल्प संशोधन किए गए हैं।

**THE TELECOMMUNICATION (BROADCASTING AND CABLE SERVICES) INTERCONNECTION
(SIXTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2010**

(No. 4 of 2010)

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 2010

F. No. 6-7/2010-B & CS.—In exercise of the powers conferred by section 36, and by sub-clauses (ii), (iii), (iv) and (v) of clause (b) of sub-section (1) and sub-section (2) of section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), read with notification of the Government of India, in the Ministry of Communication and Information Technology (Department of Telecommunications) No.39,----

- (a) issued, in exercise of the powers conferred upon the Central Government by proviso to clause (k) of sub section (1) of section 2 and clause (d) of sub-section (1) of section 11 of the said Act, and
- (b) published under notification No. S.O.44 (E) and 45 (E) dated 9th January, 2004 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3,----

the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection Regulation, 2004 (13 of 2004), namely:-

1. (1) These regulations may be called the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Sixth Amendment) Regulations, 2010.
(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In regulation 2 of the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection Regulation, 2004 (13 of 2004), (hereinafter referred to as the principal regulations), -----

(a) for sub-clause (l), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

“(l) “**head end in the sky operator**” or “**HITS operator**” means any person permitted by the Central Government to -----

- (a) distribute multi channel TV programmes in C band or Ku band -----
 - (i) by using a satellite system, to intermediaries like cable operators and not directly to subscribers; and
 - (ii) by using its own cable network, if any, to the subscribers of such cable network through Quadrature Amplitude Modulation (QAM) set top boxes, after first downlinking the signals at its terrestrial receiving station; and
- (b) provide passive infrastructure facilities like transponder space on satellite, earth station facilities, etc. to one or more multi system

operators or to any consortium of multi system operators or cable operators, for distribution of multi channel TV programmes, in C band or Ku band through QAM set top boxes, using such infrastructure facilities;”;

- (b) for sub-clause (m), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

“(m) “**multi system operator**” means any person who receives a broadcasting service from broadcasters or their authorized agencies or from a headend-in-the-sky operator and re-transmits the same to one or more cable operators or to consumers or to both and includes its authorised distribution agencies;”.

3. In regulation 3 of the principal regulations, ----

- (a) in sub-regulation 3.2., for the expression “ Multi system operators shall also on request re-transmit signals received from a broadcaster, on a non-discriminatory basis to cable operators. ”, the following expression shall be substituted, namely:-

“HITS operators and multi system operators shall also, on request, re-transmit signals received from a broadcaster, on a non-discriminatory basis to cable operators.”;

- (b) in sub-regulation 3.5, for the expression “ broadcaster/multi system operator”, wherever it occurs, the expression “broadcaster, multi system operator or HITS operator, as the case may be” shall be substituted.

4. In regulation 4 of the principal regulations, in sub-regulations 4.1 and 4.2, for the expression “broadcaster or multi system operator”, wherever it occurs, the

30/6 G1/10-3

expression “broadcaster, multi system operator or HITS operator, as the case may be” shall be substituted.

5. In regulation 13.2A of the principal regulations, -----

- (a) in sub-regulation 13.2A.1, for the words, figures, brackets and numbers “Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Fifth Amendment) Regulation, 2009 (4 of 2009)”, the words, figures, brackets and numbers “Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Sixth Amendment) Regulations, 2010 (4 of 2010)” shall be substituted;
- (b) in the proviso to sub-regulation 13.2A.2, for the words, figures, brackets and numbers “Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Fifth Amendment) Regulation, 2009 (4 of 2009)”, the words, figures, brackets and numbers “Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Sixth Amendment) Regulations, 2010 (4 of 2010)” shall be substituted;
- (c) in sub-regulations 13.2A.3 and 13.2A.4, for the words, figures, brackets and numbers “Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Fifth Amendment) Regulation, 2009 (4 of 2009)”, wherever they occur, the words, figures, brackets and numbers “Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Sixth Amendment) Regulations, 2010 (4 of 2010)” shall be substituted;
- (d) in clause (1), clause (2) and clause (3) of sub-regulation 13.2A.6, for the words, figures, brackets and numbers “Telecommunication

(Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Fifth Amendment) Regulation, 2009 (4 of 2009)", wherever they occur, the words, figures, brackets and numbers "Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Sixth Amendment) Regulations, 2010 (4 of 2010)" shall be substituted.

6. In regulation 13.2B of the principal regulations, in sub-regulations 13.2B.1 and 13.2B.2, for the words, figures, brackets and numbers "Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Fifth Amendment) Regulation, 2009 (4 of 2009)", wherever they occur, the words, figures, brackets and numbers "Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Sixth Amendment) Regulations, 2010 (4 of 2010)" shall be substituted.

SUBODH KUMAR GUPTA, Advisor (B & CS)
[No. ADVT III/4/142/10/Exty.]

Note 1: The principal regulations were published vide notification no. 8-26/2004-B&CS dated 10th December, 2004 and subsequently amended vide notifications no.3-57/2005-B&CS dated 3rd March, 2005, no.11-13/2006-B&CS dated 24th August, 2006, no. 6-4/2006-B&CS dated 4th September, 2006, no. 4-54/2007-B&CS dated 3rd September, 2007 and No. 3-21/ 2009 - B&CS dated 17th March, 2009.

Note 2: The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons of the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Sixth Amendment) Regulation, 2010.

3016 GI/10-4

Explanatory Memorandum

Background:

Government of India (Ministry of Information and Broadcasting) announced Policy guidelines for providing Headend-in-the-Sky (HITS) broadcasting service in India on 26 Nov, 2009. Pursuant to the said announcement of HITS policy, the Ministry of Information and Broadcasting requested TRAI, vide its letter dated 10th December, 2009, to revisit the relevant interconnection regulations, tariff orders, etc., in order to take a view on whether there was any amendment required in them in the interest of the service so that the benefits of the policy can be fully achieved. On the basis of the said request, TRAI initiated a consultation process on the subject "Interconnection and Tariff Issues related to HITS services". A consultation paper for the purpose was issued on 6th April, 2010. The consultation paper had grouped the issues posed for consultation into two broad categories, namely, interconnection issues and tariff issues. Issues relating to tariff have been addressed separately.

Issues for Consultation:

2. As regards Interconnection, the consultation paper has noted that the existing definition of "headend in the sky operator", as contained in the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection Regulation 2004 (13 of 2004), was a narrow definition which restricted the operations of the HITS operator to C-Band only whereas the HITS policy of the Government of India announced on 26th November, 2009, permitted HITS operations either in C-Band or Ku-Band. It was also noted in the consultation paper that the existing definition prohibited a HITS operator from serving the subscribers directly, whereas the policy guidelines now permitted the HITS operator to serve subscribers directly through its own cable

network, if any, after first downlinking the signals to its terrestrial receiving station. These changes, brought about by the HITS policy of the Government, necessitated an amendment to the definition of “headend in the sky operator”, as contained in the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection Regulation 2004 (13 of 2004)

3. The Consultation paper had also noted that, since a multi system operator can now take signals not only from broadcasters and their authorized agencies but also from a HITS operator, the definition of “multi system operator” also needed amendment. The consultation paper had, accordingly, broadly outlined the amendments required in these provisions and raised the following issues for consultation with the stake-holders:-

- (i) Are the proposed amendments to the interconnect regulations to implement HITS policy in order?
- (ii) What further amendments are required to implement HITS policy?

Stakeholder comments:

4. In all, 23 stakeholders offered their comments on the consultation paper. One stakeholder sent counter comments on the comments received from the stakeholders. Open House Discussions (OHDs) were held in Delhi, Pune, Bangaluru and Kolkata on 1st June, 2010, 3rd June, 2010, 4th June, 2010 and 8th June, 2010, respectively.

5. On the issue of the proposed amendments to the Interconnect Regulations to implement HITS policy being in order, almost all the stakeholders including

broadcasters and MSOs have expressed their agreement to the proposed amendments.

6. Considering all the aspects of the matter as emerging from the consultation process, the Authority has amended the interconnection regulation by amending the definition of the HITS operator to provide for use of both C and Ku band by these operators. Since the policy guidelines issued by the Ministry of Information and Broadcasting permit HITS operator to distribute multi channels TV programmes on its own cable network (after first downlinking the signals at its terrestrial receiving station) and also provides for HITS operator to be a passive infrastructure facility provider to other MSO or consortium of cable operators, the scope of the existing definitions of “HITS operator” and “multi system operator” have been appropriately enlarged.

7. Consequential minor amendments to regulations 3, 4, 13.2A and 13.2B have also been made.